



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2015/आश्विन 23, 1937

No. 2261]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2015/ASVINA 23, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2015

का. आ.2839(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऐजवाल के न्यायालय को दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2147 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मिजोरम राज्य था;

और जबकि, श्री आर. थंगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऐजवाल जिन्हें दिनांक 28 जुलाई, 2014 के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का. आ. 1915 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. 1915 (ड.) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, और गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्रीमती लूसी ललरिथारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऐजवाल को एतद्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस- IV (भाग-II)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Internal Security-I Divison)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2015

S.O. 2839(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S. O. 2147 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of District and Sessions Judge, Aizawl as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Mizoram for the trial of schedule offences;

And whereas, Shri R. Thanga, District and Sessions Judge, Aizawl who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S. O. 1915 (E), dated 28th July, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 28th July, 2014, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1915 (E), dated the 28th July, 2014, except as regard to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Acting Chief Justice of the Gauhati High Court at Guwahati, hereby appoints Smt. Lucy Lalrinthari, District & Sessions Judge, Aizawl as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-II)]

M. A. GANAPATHY Jt. Secy.